Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

# प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत इजरायल संबंधों का अवलोकन

**डॉ. मुकेश कुमार वर्मा* संदीप कुमार****

* सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.) भारत
** शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.) भारत

**शोध सारांश –** यह शोध पत्र वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत–इजरायल संबंधों के बहुआयामी विकास का विश्लेषण करता है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के साथ–साथ कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संबंधों का अध्ययन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई, जिसमें उच्च स्तरीय राजनयिक यात्राएँ, द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि, कृषि सहयोग के तहत उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, जल प्रबंधन समझौते, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार कार्यक्रम और रक्षा सहयोग को गति मिली। कोविड–19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग और 2023 में 'ऑपरेशन अजय' के माध्यम से इजरायल में भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी इस संबंध की गहराई को दर्शाते हैं। यह अध्ययन भारत–इजरायल संबंधों की समग्र समीक्षा प्रदान करता है और भविष्य में सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है।

**शब्द कुंजी–** भारत इजरायल संबंध, भारत इजरायल राजनयिक संबंध, भारत इजरायल रक्षा सहयोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए सरकार।

**प्रस्तावना –** भारत और इजराइल रणनीतिक साझेदार हैं। द्विपक्षीय राजनीतिक संबंध मधुर और दूरदर्शी हैं। भारत ने 17 सितंबर, 1950 को इजराइल को मान्यता देने की घोषणा की। इसके तुरंत बाद, यहूदी एजेंसी ने बॉम्बे (मुंबई) में एक आव्रजन कार्यालय स्थापित किया, जिसे बाद में एक व्यापार कार्यालय और बाद में एक वाणिज्य दूतावास में बदल दिया गया। 1992 में नियमित दूतावास खोले गए जब दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए। वर्ष 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को ऐतिहासिक जीत दिलाने के बाद नरेंद्र मोदी 26 मई, 2014 को भारत के प्रधानमंत्री बने। भाजपा ने लोकसभा में 282 सीटें (543 में से) जीतीं, 1984 के बाद पहली बार किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में इजरायल के साथ भारत के संबंधों को अत्यधिक मजबूत किया है, जो ऐतिहासिक सावधानी से एक साहसिक, रणनीतिक साझेदारी की ओर बदलाव को दर्शाता है। उनकी नीति रक्षा, प्रौद्योगिकी, कृषि और आतंकवाद विरोधी पर केंद्रित है, जबकि फिलिस्तीन के लिए भारत के पारंपरिक समर्थन को संतुलित करती है।

हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत–इजराइल संबंधों पर विद्वानों ने गहन शोध किया है, यथा– कुमारास्वामी (2023) ने मोदी युग में इस संबंध में आए 'सैद्धांतिक बदलाव' को रेखांकित किया, जबकि आर्य (2022) ने इसे एक 'रणनीतिक पुनर्संरेखण' बताया। कार्टसेव (2023) ने 2014 के बाद के द्विपक्षीय संबंधों की तुलना ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत की। कुमार (2019) ने मोदी की विदेश नीति में इजराइल को मिली प्राथमिकता का विश्लेषण किया, जबकि दाश (2020) ने रक्षा और कृषि जैसे नए आयामों पर प्रकाश डाला। भादुड़ी (2023) ने 75 वर्षों के संबंधों के विकासक्रम में मोदी युग को महत्वपूर्ण मोड़ बताया। बिरवाडकर (2016) ने फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की नीति में बदलाव का अध्ययन किया, जबकि श्रीरामुलु (2016) ने मोदी की विदेश नीति के समग्र स्वरूप में इजराइल के स्थान को रेखांकित किया। कौरा (2019) ने इस संबंध को 'परिवर्तनकारी बदलाव' की संज्ञा दी, और ब्लारेल (2021) ने पश्चिम एशिया नीति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्वों की पहचान की। इसी दिशा में शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत शोधपत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत–इजराइल संबंधों का एक बहुपक्षीय अवलोकन किया गया है।

**अनुसंधान योजना –**इस शोध कार्य का उद्देश्य वर्ष 2014 के पश्चात् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत इजरायल संबंधों का अवलोकन करना है, जिसके अन्तर्गत दोनों देशों के मध्य राजनीतिक सम्बन्ध, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध, कृषि सहयोग, जल संसाधन प्रबंधन और विकास सहयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) की दिशा में सहयोग, रक्षा क्षेत्र में सहयोग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग, लोगों से लोगों के बीच संबंध आदि का अध्ययन सम्मिलित है। प्रस्तुत शोधपत्र गुणात्मक सूचनाओं पर आधारित है, जिन्हें शोधकर्ता द्वारा इन सूचनाओं को क्रमबद्ध कर शोध समस्या का विश्लेषण किया गया है।

**शोध समस्या का विश्लेषण–**शोधकर्ता द्वारा यहाँ शोध समस्या का क्रमबद्ध विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, यथा–

**राजनीतिक संबंधों का अवलोकन –** प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 4–6 जुलाई, 2017 को इजरायल की पहली ऐतिहासिक यात्रा की, जिसके दौरान संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया गया। जनवरी 2018 में, पीएम नेतन्याहू ने 14–19 जनवरी को भारत की वापसी यात्रा की। दोनों यात्राओं के दौरान संयुक्त बयान जारी किए गए। इससे पूर्व भारत के

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अक्टूबर 2015 में इजरायल की राजकीय यात्रा की, जबकि इजरायल के तत्कालीन राष्ट्रपति रियुवेन रिवलिन ने नवंबर 2016 में भारत की राजकीय यात्रा की। भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह, एस.एम. कृष्णा और सुषमा स्वराज ने भी क्रमश: वर्ष 2000, 2012 और 2016 में इजरायल का दौरा किया।

वर्ष 2022-23 में, दोनों देशों ने संयुक्त रूप से द्विपक्षीय संबंधों के पूर्ण राजनयिक स्तर तक पहुंचने के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाया। 11 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री (पीएम) बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और उन्हें छठी बार इजरायल के पीएम चुने जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी और पीएम नेतन्याहू ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 8 फरवरी, 2023 को भी बात की।

24 अगस्त, 2023 को पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री को फोन करके चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने पर बधाई दी। 10 अक्टूबर, 2023 को पीएम नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर के हमलों के बाद इजरायल की स्थिति पर अपडेट देने के लिए प्रधानमंत्री को फोन किया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी ने 19 दिसंबर, 2023 को क्षेत्र की स्थिति और समुद्री सुरक्षा के बारे में भी बात की। 6 जून, 2024 को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार भारत के पीएम चुने जाने पर बधाई दी।

**आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध –** 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद से, भारत-इजराइल द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों में तेजी से प्रगति हुई है। 1992 में लगभग 200 मिलियन अमरीकी डॉलर (जिसमें मुख्य रूप से हीरे शामिल हैं) से, व्यापारिक व्यापार में विविधता आई और वित्त वर्ष 2022-23 में यह लगभग 10.77 बिलियन अमरीकी डॉलर (रक्षा को छोड़कर) तक पहुँच गया, जिसमें भारतीय निर्यात लगभग 8.45 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-मार्च) में, द्विपक्षीय व्यापार 6.53 बिलियन अमरीकी डॉलर (रक्षा को छोड़कर) था, जिसमें भारत का निर्यात 4.52 बिलियन अमरीकी डॉलर और इजराइल का निर्यात 2.0 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

भारत एशिया में इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हालांकि, द्विपक्षीय व्यापारिक व्यापार में मुख्य रूप से हीरे, पेट्रोलियम उत्पाद और रसायनों का प्रभुत्व है, हाल के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और उच्च तकनीक वाले उत्पादों, संचार प्रणालियों, चिकित्सा उपकरण आदि जैसे क्षेत्रों में व्यापार में वृद्धि देखी गई है।

अप्रैल, 2000 से अप्रैल, 2024 तक भारत से इजरायल में संचयी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) लगभग 396 मिलियन अमरीकी डालर था अप्रैल 2000 से मार्च 2024 की अवधि में, इजरायल से भारत में प्रत्यक्ष एफडीआई लगभग 314.87 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2022 में, भारत के अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (APSEZ) ने 1.18 अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ इजरायल सरकार से हाइफा पोर्ट कंपनी लिमिटेड का अधिग्रहण किया।

**कृषि –** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत और इजरायल के मध्य कृषि क्षेत्र में भी अभूतपूर्व सहयोग बढ़ा है। दोनों पक्षों के मध्य 10 मई, 2006 को हस्ताक्षरित कृषि में सहयोग के लिए 'एक व्यापक कार्य योजना' के तहत, MASHAV (इजरायल के विदेश मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केंद्र) और CINADCO (इजरायल के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास सहयोग केंद्र) के माध्यम से द्विपक्षीय परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि दोनों पक्षों के बीच कृषि सहयोग को एक 3-वर्षीय कार्य योजनाओं के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाता है, जिसमें 3-वर्षीय कार्य योजनाएँ विकसित की जाती हैं। 5वीं 3-वर्षीय कार्य योजना (2021- 2023) पर 24 मई को हस्ताक्षर किए गए, जिसके अंतर्गत 13 भारतीय राज्यों में 31 कृषि उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। इजरायल भारत को शुष्क कृषि के विकास के लिए तकनीकी हस्तांतरण कर रहा है।

**जल संसाधन प्रबंधन और विकास सहयोग –** जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग को नवंबर, 2016 में हस्ताक्षरित एक समझौते के रूम में औपचारिक रूप दिया गया था। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने (i) भारत में जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभियान और (ii) यूपी जल निगम के सुधारों पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। अक्टूबर 2018 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री की इजराइल यात्रा के दौरान, पंजाब सरकार और मेकोरोट (इजराइल नेशनल वाटर कंपनी) ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत मेकोरोट पंजाब के लिए जल संरक्षण और प्रबंधन योजना तैयार करेगा। मई 2023 में, दोनों देशों ने क्रमश: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए।

**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) –** दोनों देशों के मध्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए सहयोग बढ़ाने की दिशा में वर्ष 1993 के अंतर्गत हस्ताक्षरित एस एंड टी सहयोग समझौतेय के तहत स्थापित एस एंड टी पर संयुक्त समिति, एस एंड टी में भारत-इजराइल सहयोग की देखरेख करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर दसवीं संयुक्त आयोग बैठक 25 जुलाई, 2022 को आयोजित की गई, जिसके तहत भारत-इजराइल संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम (IIJRC) 2023 का शुभारंभ किया गया, जिसमें खाद्य सुरक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन और कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अनुप्रयोग के क्षेत्र में प्रस्ताव मांगे गए।

जुलाई, 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान, भारत-इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और नवाचार निधि (I4F) की स्थापना के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत और राष्ट्रीय तकनीकी नवाचार प्राधिकरण, इजराइल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता ज्ञापन, पांच वर्षों (2018-2022) में प्रत्येक पक्ष से 20 मिलियन अमरीकी डॉलर के योगदान के साथ, भारतीय और इजराइली उद्यमों को कृषि, जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और आईसीटी जैसे प्राथमिकता वाले प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरू करने में सक्षम बनाता है। वर्ष 2023 में दोनों पक्षों ने इस I4F कार्यक्रम को अगले 5 साल (2023-27) की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। अब तक, I4F ने तीस अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है, जिसमें कम लागत वाले, उच्च दक्षता वाले सौर जल पंपिंग समाधान, ड्रोन का पता लगाने और बेअसर करने की प्रणाली, और प्रारंभिक पहचान के लिए एक AI-आधारित परियोजना शामिल है।

सितंबर 2020 में, इजराइल के स्टार्टअप नेशन सेंट्रल और भारत के इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी (iCREATE) ने

नवाचार और तकनीकी सहयोग में तेजी लाने के लिए एक द्विपक्षीय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। मई 2023 में, भारत और इजराइल ने इजराइल के 'रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय' और भारत की 'वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद' के मध्य औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग करने की दिशा में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

**रक्षा क्षेत्र में सहयोग –** भारतीय नौसेना के जहाजों द्वारा नियमित सद्भावना यात्राओं के हिस्से के रूप में, पश्चिमी बेड़े के तीन भारतीय नौसैनिक जहाजों ने मई में हाइफा में एक बंदरगाह कॉल किया। नौसेना प्रशिक्षण जहाज आईएनएस तरंगिनी ने सितंबर 2018 में हाइफा में एक बंदरगाह कॉल किया। नौसैनिक अभ्यासों के अलावा, भारतीय वायु सेना ने इजराइल में अक्टूबर 2021 में आयोजित एक बहुपक्षीय वायु सेना अभ्यास, ब्लू फ्लैग–2021 में भाग लिया।

3 मार्च, 2023 को भारत के रक्षा मंत्री ने इजराइली रक्षा मंत्री योव गैलेंट से बात की। यह दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच पहली बातचीत थी। इसके अलावा, तत्कालीन इजराइली रक्षा मंत्री बेंजामिन गैंट्ज ने भी जून 2022 में भारत का दौरा किया। भारत के तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल एम.एम. भारत के वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने अगस्त 2021 में इजराइल का दौरा किया था। रक्षा पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक पिछली बार अक्टूबर, 2021 में इजराइल में हुई थी।

**ऑपरेशन अजय –**7 अक्तूबर, 2023 के आतंकवादी हमलों के बाद इजराइल में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने और स्थिति की निगरानी करने तथा भारतीय नागरिकों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए दूतावास में 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। इसके अलावा, इजराइल में सभी भारतीयों की सहायता के लिए दूतावास में 24 घंटे की आपातकालीन हेल्पलाइन भी स्थापित की गई। 12 अक्टूबर, 2023 को भारत सरकार ने उन भारतीयों की वापसी की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया जो इजराइल से भारत वापस जाना चाहते थे। 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर, 2023 के बीच ऑपरेशन अजय के तहत संचालित छह विशेष उड़ानों में 1,300 से अधिक भारतीय नागरिक भारत लौटे।

**स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग –** 21 दिसंबर, 2020 को भारत और इजराइल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा में सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान और विकास सहित द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने की परिकल्पना की गई है। भारत और इजराइल ने कोविड–19 महामारी से निपटने में सहयोग किया और कोविड–19 टीकाकरण प्रमाणपत्रों को पारस्परिक रूप से मान्यता देने पर सहमति व्यक्त की।

**लोगों से लोगों के बीच संबंध –** इजराइल में लगभग 26,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से अधिकांश देखभाल करने वाले हैं, जिन्हें इजराइली बुजुर्गों ने उनकी देखभाल के लिए नियुक्त किया हैय हीरा व्यापारी, निर्माण और कृषि क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिक, आईटी पेशेवर और छात्र। जुलाई 2017 में इजराइल की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री ने तेल अवीव प्रदर्शनी मैदान में इजराइल में काम कर रहे लगभग 8,000 पीआईओ और भारतीय नागरिकों की एक सभा को संबोधित किया। मार्च 2018 में नई दिल्ली और तेल अवीव के बीच प्रति सप्ताह 5 उड़ानों के साथ एयर इंडिया की उड़ानों की शुरुआत से पर्यटन और लोगों से लोगों के बीच संपर्क में काफी वृद्धि हुई है। इजराइल में लगभग 900 भारतीय छात्र अध्ययन कर रहे हैं।

**निष्कर्ष –** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत–इजराइल संबंधों में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। राजनीतिक स्तर पर, मोदी की 2017 में पहली इजराइल यात्रा और नेतन्याहू की भारत यात्रा ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया। आर्थिक संबंधों में वृद्धि हुई, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार 2022–23 में 10.77 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया। कृषि क्षेत्र में, इजराइल ने 13 भारतीय राज्यों में 31 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए। जल प्रबंधन, विज्ञान–प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग भी बढ़ा, जिसमें संयुक्त अनुसंधान और हथियार व्यापार शामिल हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में कोविड–19 सहयोग और 2023 में ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से 1,300 भारतीयों की सुरक्षित वापसी उल्लेखनीय है। लोगों के बीच संपर्क बढ़ा, जिसमें प्रवासी श्रमिक, छात्र और यहूदी भारतीय समुदाय शामिल हैं। यह साझेदारी अब रक्षा, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास पर केंद्रित है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :–**

1. Arya, N. K. (2022). India-Israel Relations in the Modi Era: Emerging Contours of Cooperation. Available at SSRN 4032468.
2. Bhaduri, A. (2023). The Evolution of India-Israel Relations: 1948-2023. Ukrainian Policymaker, 13(13), 4-12.
3. Birvadker, O. (2016). Changes in Indian foreign policy: The case of Israel and the Palestinians. Strategic Assessment, 18(4), 85-95.
4. Blarel, N. (2021). Modi looks West? Assessing change and continuity in India's Middle East policy since 2014. International Politics (The Hague), 59(1), 90.
5. Dash, D. K. (2020). Indo-Israel Relations: New Dimensions Under Modi Era.
6. Kartsev, K. (2023). India-Israel Relations since independence with special emphasis on the post 2014 period.
7. Kaura, V. (2019). Indo-Israeli relations in the Modi era: a transformative shift. Israel Affairs, 25(2), 217-233.
8. Kumar, D. (2019). India-Israel Relations under Narendra Modi. International Journal of Research in Social Sciences, 9(4), 791-802.
9. Kumaraswamy, P. R. (2023). India's Balancing Act on the Israel-Hamas Conflict. Indian Foreign Affairs Journal, 18(1/2), 15-32.
10. Kumaraswamy, P. R. (2023). Indo-Israeli relations: changes under Narendra Modi. Global Discourse, 13(1), 70-83.
11. Sreeramulu, N. (2016). Foreign Policy of Narendra Modi Prime Minister of India. Editorial Board, 5(1), 97.

**********